संक्षेप में

केंद्रीय अनुदान से राज्यों को मिली मदद : इक्रा

रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि बिक्री कर संग्रहण में मामूली वृद्धि तथा केंद्र से अनुदान में अच्छी खासी वृद्धि के चलते राज्यों को काफी मदद मिली और नोटबंदी के बावजूद भी उन्हें अपनी व्यय वृद्धि में ज्यादा कटौती नहीं करनी पड़ी। एजेंसी का कहना है कि उच्च पूंजीगत व्यय तथा ऋण विस्तार से भी वित्त वर्ष 2017 में राज्यों के राजकोषीय घाटे व उधारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इक्रा समूह के प्रमुख (कॉरपोरेट सेक्टर रेटिंग) जयंत राय ने कहा, 'नोटबंदी का असर राज्यों के कुछ चुनिंदा राजस्व मदों पर हुआ जिनमें स्टांप एवं पंजीकरण संग्रह तथा भू राजस्व शामिल है। हालांकि, बिक्री कर संग्रहण में मामूली वृद्धि तथा केंद्र से अनुदान में बढ़ोतरी के चलते उन्हें खर्च वृद्धि में अधिक कटौती नहीं करनी पड़ी। *भाषा*

गुजरात में बनेगा पहला रेल विश्वविद्यालय

देश का पहला राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। रेल राज्य मंत्री राजेन गोहांई ने बताया कि रेल मंत्रालय ने गुजरात के वड़ोदरा में एक रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। इस संबंध में एक आरंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और फिर ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए मैसर्स राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। गोहांई ने बताया कि विश्वविद्यालय कब तक काम शुरू करेगा, इसकी अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। *भाषा*

वेतन ढांचा बदलेगा स्टेट बैंक

अनूप रॉय
मुंबई, 17 मार्च

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) वेतन ढांचे का पुराना प्रस्ताव बहाल कर सकता है, जिसे कर्मचारी संगठनों के दबाव में अब तक लागू नहीं किया जा सका। इस ढांचे में अधिकारियों का वेतनमान 4 से 7 पैमाने पर निर्धारित व परिवर्तनीय घटकों में विभाजित किया जाएगा। निर्धारित वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और शेष प्रदर्शन से जुड़ा परिवर्तनीय वेतन होगा। अगर नया ढांचा स्वीकार किया जाता है तो यह सहयोगी बैंकों पर भी लागू होगा, जब वे 1 अप्रैल को एसबीआई का हिस्सा बन जाएंगे।

स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी परिवर्तनीय वेतन ढांचा चाहते हैं, क्योंकि उनके कठिन परिश्रम का कोई पुरस्कार नहीं मिलता। नए वेतन ढांचे में जरूरी नहीं है कि भुगतान मौजूदा पैकेज से कम हो, लेकिन इसमें इस ढांचे से ज्यादा वेतन होने की गुंजाइश होगी।

स्टेट बैंक इस व्यवस्था को कुछ समय से पेश करने की कोशिश कर रहा है और वेतन को लेकर बातचीत में इसे रखा जा रहा है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल इस बार मामला कुछ अलग हो सकता है। यूनियनों का कहना है कि परिवर्तनीय ढांचा अब लगता है कि अवश्यंभावी हो गया है। यूनियन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'अब ऐसा लगता है कि विलय के बाद हम इस ढांचे को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बैंक प्रबंधन अधिकारियों को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाएगा और इसके बाद अलग ढांचा लागू हो जाएगा।'

सहयोगी बैंकों ने पहले ही कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की है। उम्मीद की जा रही है कि यह योजना व्यापक रूप से स्वीकार्य होगी। योजना उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है या सेवा के 5 साल ही बचे हैं। यूनियनों ने कर्मचारियों से इस योजना को खारिज करने की अपील की है। लेकिन यूनियनों के लिए कर्मचारियों को मनाना मुश्किल होगा। यूनियनों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तमाम शाखाएं बंद कर दी जाएंगी या विलय के बाद उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया जाएगा और मौजूदा कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण होगा।

मार्च 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक उसके कर्मचारियों की संख्या 2,07,739 है। स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर में 14,892, स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐंड जयपुर में 13,529, स्टेट बैंक आफ मैसूर में 10,650, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में 17,414 और स्टेट बैंक आफ पटियाला में 11,175 कर्मचारी हैं। आखिरी दो बैंक सूचीबद्ध नहीं हैं।

एक सहयोगी बैंक के अधिकारी ने कहा, 'सहयोगी बैंकों के साथ व्यवहार बड़े पैमाने पर इस बात पर निर्भर कि वीआरएस योजना कितनी सफल रहती है। अगर यह विफल रहती है तो कर्मचारियों के साथ खराब वर्ताव हो सकता है।' अगर पहले के विलय को संकेत माना जाए तो सहयोगी बैंकों के कर्मचारियों के साथ कुछ भेदभाव की संभावना बनती है। इस अनुमान के कारण यूनियन इस कदम का विरोध कर रहे हैं और विरोध जल्द ही तेज हो सकता है। स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आफ इंदौर के एसबीआई के साथ विलय के बाद प्रबंधन ने विलय हुई इकाइयों के अधिकारियों की वरिष्ठता कम कर दी थी।

बैंकों के विलय के बाद संभावित बदलाव

- बैंक परिवर्तनीय वेतन ढांचा लागू करना चाहता था, जिसे कर्मचारी संगठनों के दबाव में नहीं लागू किया जा सका
- संगठनों का कहना है कि विलय के बाद इस कदम को रोकना उनके लिए होगा मुश्किल

बीएस बातचीत

'सितंबर से लागू हो जीएसटी'

उम्मीद की जा रही है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री **हसीब द्राबू** चाहते हैं कि इसे 2 महीने देरी से लागू किया जाए। **दिलाशा सेठ** से बातचीत में उन्होंने कहा कि तैयारियों के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए। प्रमुख अंश...

1 जुलाई की तिथि से कितने संतुष्ट हैं?
जीएसटी 1 जुलाई से लागू करना संभव है, लेकिन यह 1 सितंबर से लागू होना चाहिए।

क्यों?
राज्यों के पास पर्याप्त समय होगा। अभी भी हम नियम नहीं जानते। परिचालन संबंधी तमाम कठिनाइयां हैं। सूचना तकनीक व्यवस्था का परीक्षण करना होगा। छह महीने का समय मिलेगा तो मदद मिलेगी। जीएसटी लागू करने के लिए 1 सितंबर से बेहतर समय होगा।

परिषद ने जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे दी। अब कितनी तेजी से इस पर आगे बढ़ा जा सकेगा?
तीन प्रमुख विधेयकों केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) परिषद ने पारित कर दिया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह केंद्रीय वित्त मंत्री (अरुण जेटली) इसे संसद में पेश करेंगे। 31 मार्च तक सभी कानून को अंतिम रूप दिए जाने व उसे अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है।

लग्जरी कारों व एरेटेड पेय पर 15 प्रतिशत अधिकतम उपकर तय करने की क्या वजह है?
प्रावधान करने से यह कानून का रूप लेगा। इसके पीछे यह विचार है कि समग्र दर 40 प्रतिशत रखी जाए, जिसमें 28 प्रतिशत जीएसटी और 12 प्रतिशत उपकर है। उपकर राज्यों के कर की भरपाई के लिए है। इसकी सीमा 15 प्रतिशत तय की गई है,जिससे 28 विधायिकाओं को इसे बढ़ाने की जरूरत न पड़े।

जम्मू कश्मीर विधानसभा में कब तक विधेयक पारित हो जाएगा?
जल्द ही कर लिया जाएगा।

रेलवे ने वापस मांगा सेवा शुल्क

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 17 मार्च

वित्त मंत्रालय की ओर से भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी), भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) और इरकॉन इंटरनैशनल (इरकॉन) की सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरू किए जाने के साथ आईआरसीटीसी के सेवा शुल्क के नुकसान का मामला रेलवे अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

सरकार ने नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नोटबंदी के समय सेवा शुल्क माफ करने की घोषणा की थी।

रेल मंत्रालय ने सालाना आधार पर होने वाले 500 करोड़ रुपये सेवा शुल्क के नुकसान की भरपाई की मांग वित्त मंत्रालय से की है। आईआरसीटीसी इसमें से आधे सेवा शुल्क का भुगतान रेलवे को करता है। अधिकारी ने कहा कि मर्चेंट बैंकर नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईडीएफसी ने इसके लिए प्रस्तुति दी है।

सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने इस सिलसिले में रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दाखिल करने के लिए 16 मार्च को अंतिम तिथि तय किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले महीने पेश किए गए बजट में इन कंपनियों की सूचीबद्धता की घोषणा की थी। रेलवे ने वित्त मंत्रालय को सेवा शुल्क के मसले पर बजट के पहले ही पत्र लिखा था।

सेवा शुल्क वापस किए जाने की मांग को लेकर लिखे गए पत्र के बारे में पूछे जाने पर रेलवे के नए वित्त आयुक्त बीबी वर्मा ने कहा, 'हम इन तीनों कंपनियों के बेहतर मूल्यांकन की उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल सेवा शुल्क माफ किया जाना चिंता का विषय है क्योंकि इससे आईआरसीटीसी को सालाना 500 करोड़ रुपये के करीब राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा।'

आईआरसीटीसी वातानुकूलित टिकट की बुकिंग पर 40 रुपये प्रति टिकट और शयनयान की बुकिंग पर 20 रुपये प्रति टिकट सेवा शुल्क लेता है।

2015-16 में आईआरसीटीसी को इससे 551 करोड़ रुपये फायदा हुआ था, जो 2014-15 के 256 करोड़ रुपये की तुलना में 115 प्रतिशत ज्यादा है।

रेलवे बोर्ड के सदस्य (यातायात) मोहम्मद जमशेद ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्रालय इस संबंध कुछ करेगा और हमने इस सिलसिले में मंत्रालय को पत्र भेजा है। सेवा शुल्क के रूप में आईआरसीटीसी को हर महीने औसतन 40 करोड़ रुपये मिलते हैं, जिनमें से करीब 20 करोड़ रुपये हिस्सा रेलवे का होता है।

घाटे की भरपाई

- रेल की तीन कंपनियों की सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरू करने के साथ सेवा शुल्क के नुकसान का मसला बना चिंता का विषय
- नोटबंदी के बाद सेवा शुल्क खत्म होने से 500 करोड़ रुपये सालाना नुकसान की भरपाई की मांग वित्त मंत्रालय से की गई है

अगले वित्त वर्ष में दोगुना हो जाएगा राज्यों का कर्ज

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 17 मार्च

कर्ज के बोझ से दबे कुछ राज्यों पर 2017-18 में कर्ज का संकट और गहरा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक राज्यों पर कर्ज का बोझ अगले वित्त वर्ष में बढ़कर दोगुना हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 में कर्ज 31,820 करोड़ रुपये था जो 2017-18 में 70,240 करोड़ रुपये हो जाएगा। 2018-19 में कर्ज बढ़कर 1,19,900 करोड़ रुपये होगा।

रेटिंग एजेंसी इक्रा की हाल की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि राज्य सरकारों की सकल बाजार उधारी 2016-17 के 3.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 4.5 लाख करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है।

इक्रा में कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग के ग्रुप हेड जयंत रॉय ने कहा, 'उधारी की ज्यादा राशि की वजह सभी राज्यों की बड़े पैमाने पर पुनर्भुगतान बाध्यता है। कोई भी राज्य कर्ज की अतिरिक्त राशि के भुगतान की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसी के पास अतिरिक्त राशि नहीं है। ऐसे में भुगतान का काम नए सिरे से उधारी लेकर करना होगा।' उन्होंने कहा कि बहरहाल सकल जीडीपी और राजस्व प्राप्तियों को देखा जाए तो कर्ज की राशि सीमा के भीतर है और यह चिंताजनक नहीं है।

कर्ज के पुनर्भुगतान का बोझ कर्ज में डूबे राज्यों खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर पर ज्यादा होगा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में महाराष्ट्र पर बाजार से कर्ज का बोझ करीब 17,760 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो 2017-18 के 8,520 करोड़ रुपये का दोगुना होगा।

उत्तर प्रदेश के मामले में कर्ज तीन गुना बढ़ेगा, क्योंकि बाजार से लिए गए कर्ज के भुगतान का बोझ 2017-18 के 4,420 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 12,690 करोड़ रुपये हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल में बाजार से लिए कर्ज के पुनर्भुगतान का बोझ 2016-17 के 3,200 करोड़ रुपये की तुलना में 2017-18 में 11,610 करोड़ रुपये हो जाएगा।

फिलहाल सुस्त नहीं होगा निर्यात

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 17 मार्च

कारोबारियों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये की मजबूती से फिलहाल निर्यात पर बुरा असर पड़ने की संभावना कम है, जो फरवरी में 17 प्रतिशत बढ़ा है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की घोषणा के बावजूद गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हाल के महीनों में मजबूती बरकरार रखते हुए चालू कैलेंडर वर्ष में रुपये 3.4 प्रतिशत मजबूत हुआ है।

वहीं दूसरी ओर लगातार 6 महीने से निर्यात बढ़ रहा है। उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में निर्यात 5 साल में सबसे तेजी से बढ़ा है।

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'मुद्रा से कोई सहयोग न मिलने के बावजूद निर्यात बढ़ा है।' उनका मानना है कि निर्यात में तेजी जारी रहेगी, भले ही रुपये में मजबूती बनी रहे।

डॉलर की तुलना में रुपये का प्रदर्शन एशिया की तीसरी बेहतरीन मुद्रा के रूप में है। रुपया अभी कोरिका के वॉन और ताइवान के डॉलर से पीछे है, जो क्रमश: 5.4 प्रतिशत और करीब 5 प्रतिशत मजबूत हुए हैं।

कुछ अन्य वजहों के साथ प्रमुख राज्यों में मोदी सरकार का चुनाव में शानदार प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण वजह है, जिसके चलते रुपये में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'कारोबार के हिसाब से देखें तो भारत की कठिन स्थिति है, क्योंकि यह सिर्फ उभरती बाजार अर्थव्यवस्था है, जहां मुद्रा मजबूत हो रही है।'

बहरहाल बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने नीतिगत दरें 25 आधार अंक बढ़ा दी हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आने वाले महीनों में रुपया सुस्त हो सकता है। फरवरी में अचानक निर्यात में तेज उछाल की वजह कम बेस इफेक्ट और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। इसकी वजह से इंजीनियरिंग व पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में तेजी आई है, जो विदेशी मुद्रा कमाने वाले दो प्रमुख जिंस हैं।

रुपये के मजबूत होने से चिंता नहीं

- कारोबारियों और विश्लेषकों का मानना है कि कम अवधि के हिसाब से रुपये की मजबूती का निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा
- चालू कैलेंडर वर्ष में डॉलर के मुकाबले रुपया 3.4 प्रतिशत मजबूत हुआ है
- निर्यात भी लगातार 6 महीने से बढ़ रहा है, फरवरी में निर्यात में पिछले 5 साल की तुलना में सर्वाधिक तेजी

Bharat Heavy Electricals Limited
यूनिटः तिरुच्चिराप्पल्लि

पी.पी.जी.आई नालीदार चादरें (PPGI CORRUGATED SHEETS) की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता

बीएचईएल तिरुच्चिराप्पल्लि की ओर से **प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट्स (Pre-Painted Galvanised Steel Sheets)** की नियमित आधार पर आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं (केवल निर्माताओं) से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसके लिए टेंडर दस्तावेज एवं पूर्ण विवरण बीएचईएल वेबसाइट **http://www.bhel.com** (टेंडर अधिसूचना पेज) या सरकारी निविदा वेबसाइट **http://tenders.gov.in** (पब्लिक सेक्टर यूनिट>भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पेज) पर संदर्भ संख्या **NIT_31913** या **http://eprocure.gov.in** पर संदर्भ संख्या **2017_BHEL_200067_1** से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक पार्टियों बीएचईएल ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम **https://bheleps.buyjunction.in** के माध्यम से अपनी पेशकश प्रस्तुत कर सकते हैं

टेंडर हेतु सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन/समयावधि विस्तार/स्पष्टीकरण आदि केवल उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे और अन्य किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। बोलीदाता स्वयं को अपडेट करने हेतु नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट देखें।

Sr. Engineer / MM / BOI, BHEL, Tiruchirappalli - 620 014 (TN).
Ph. (**0431) 2577897 / 4086**; Fax: **2520719**; email: **sachinsaini@bheltry.co.in**

नारद स्टिंग की सीबीआई जांच

बीएस संवाददाता/भाषा
कोलकाता, 17 मार्च

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद स्टिंग मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच के आज आदेश दिए। इसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और मंत्री एक संदिग्ध कंपनी का पक्ष लेने के मामले में कथित तौर पर घूस लेते नजर आए थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिता म्हात्रे और न्यायमूर्ति टी चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सीबीआई को 24 घंटे के भीतर स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित सभी सामग्री और उपकरण अपने कब्जे में लेने और 72 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच को निष्कर्ष पर पहुंचाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद जरूरत पड़ने पर सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करे और उसके बाद औपचारिक जांच शुरू करे। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग के टेप विभिन्न समाचार संगठनों को जारी किए गए थे। इसमें कुछ नेता कथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाई दिए थे। खंडपीठ ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, चंडीगढ़ की उस रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि इन टेपों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह अदालत का अधिकार है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। उन्होंने सवाल किया कि सभी यह जानते हैं कि 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा कार्यालय द्वारा इस वीडियो फुटेज को जारी किया गया था। राज्य भाजपा अध्यक्ष ने भी कहा था कि नारद मामले के फैसले की घोषणा उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद की जाएगी। आखिर वह इस बात को कैसे जानते थे? नारद न्यूज के संपादक मैथ्यू सैम्यूल ने अदालत को बताया कि रिकॉर्डिंग आईफोन की मदद से की गई और उसे लैपटॉप में डाला गया जहां से उसे एक पेन ड्राइव में लिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक समिति ने इन सभी उपकरणों को कब्जे में ले लिया। अदालत ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, वे मंत्री, सांसद और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए यह उचित होगा कि प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए।

बीएस सूडोकू 2766

परिणाम संख्या 2765

9					6	5		
		5					1	8
	4				8			
					9	2		4
	7	2				9	6	
4		1	8					
			9				4	
3	2					8		
		9	3					7

2	6	4	3	5	7	1	9	8
8	9	3	6	1	4	5	2	7
1	5	7	9	8	2	4	3	6
9	7	2	1	4	5	6	8	3
6	4	8	7	2	3	9	5	1
5	3	1	8	6	9	7	4	2
3	8	6	5	9	1	2	7	4
7	2	5	4	3	6	8	1	9
4	1	9	2	7	8	3	6	5

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

जे.के. सीमेंट लिमिटेड
सीआईएन. : L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालयः कमला टावर, कानपुर नगर– 208001 उत्तरप्रदेश, भारत
फोन :+91-512-2371478/81, फैक्स : +91-512-2399854
ईमेल : shambhu.singh@jkcement.com, वेबसाइट :www.jkcement.com

डाक मतपत्र परिणाम

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 सपठित कम्पनीज(प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014, समय–समय पर संशोधित एवं सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग दायित्वो एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन 2015('लिस्टिंग नियमन') के अंर्तगत डाक मतपत्र सूचना दिनांक 4 फरवरी, 2017में प्रस्तावित निम्न संकल्प कम्पनी के सदस्यों द्वारा डाक मत पत्र वोटिंग जिसमें ई–वोटिंग सम्मिलित है, पारित किया गया ।

संकल्प का प्रकार	संकल्प का विवरण
विशेष संकल्प	श्री पाल हेन्ज ह्यूजेनटोबलर, निदेशक (DIN: 00452691) द्वारा दी जा रही विशिष्ट सलाहकार सेवाओं की संविदा का अनुमोदन

मे0 रीना जाखोदिया व एसोसियेट्स, कंपनी सचिव(FCS No.F 6435, C.P. No. 6083) की सुश्री रीना जाखोदिया की स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट दिनांक 17 मार्च, 2017 के आधार पर डाकमत पत्र के मतों का परिणाम 17 मार्च, 2017 को सायं 7.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किये गये जो निम्न हैं:–

विशेष संकल्प

	वैद्य मतों की संख्या			प्रतिशत
विवरण	डाक मत	ई वोटिंग	कुल	
सहमति	204699	53612648	53817347	86.87
असहमति	132	8137509	8137641	13.13
कुल	204831	61750157	61954988	100.00

अतः उपरोक्त मामले से सम्बन्धित विशेष संकल्प आवश्यक बहुमत के साथ शेयरधारकों द्वारा पारित किया गया। स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट एवं मत पत्र परिणाम से सम्बन्धित सूचना कम्पनी की वेबसाइटwww.jkcement.com पर उपलब्ध है।

कृते जे.के. सीमेंट लिमिटेड
(शम्भू सिंह)
सहायक उपाध्यक्ष (विधि) एवं कंपनी सचिव

स्थान : कानपुर
दिनांक : 17.03.2017

1 अरब डॉलर का कोष बनाएंगे भारत-रूस

भारत और रूस बुनियादी ढांचा क्षेत्र और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में आपसी निवेश प्रोत्साहन के लिए एक अरब डॉलर का कोष बना रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि दोनों देश इस कोष में 50-50 करोड़ डॉलर का योगदान करेंगे। रूस का कोष रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) के जरिए आएगा, जबकि भारत का योगदान राष्ट्रीय निवेश एवं संरचना कोष (एनआईआईएफ) के जरिए होगा। सीतारामन ने रूस और भारत द्वारा आपसी आर्थिक संपर्क बढ़ाने तथा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रोत्साहन उपायों पर चर्चा की। *भाषा*

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

दिल्ली

अनाज : गेहूं म.प्र. (देशी) 2350-2650, गेहूं दड़ा (मिल के लिए) 1850-1860, चक्की आटा (डिलिवरी) 1920-1950, आटा राजधानी (10 किग्रा) 260, शक्तिभोग (10 किग्रा) 260, रोलर फ्लोर मिल 1030-1040 (50 किग्रा), मैदा 1130-1140 (50 किग्रा), सूजी 1250-1260 (50 किग्रा), बासमती चावल लाल किला 10700, श्रीलाल महल 11300, सुपर बासमती चावल 9700, बासमती कॉमन नई 7600-7700, चावल पूसा (1121) 6150-7600, परमल कच्चा 2275-2300, परमल वैन्ड 2400-2450, सेला 3100-3200, चावल आईआर-आठ 2025-2050, बाजरा 1400-1410, ज्वार पीली 1650-1700, सफेद 3350-3550, मक्का 1540-1550, जौ 1550-1570,

दलहन : उड़द 6500-7400, उड़द छिलका (स्थानीय) 6700-6800, उड़द बेहतरीन 6800-7300, धोया 7200-7400, मूंग 5100-5300, दाल मूंग छिलका (स्थानीय) 5600-5800, मूंग धोया स्थानीय 6200-6700, बढ़िया किस्म 6700-6900, मसूर छोटी 4700-4850, बोल्ड 4750-4950, दाल मसूर स्थानीय 5100-5600, बेहतरीन क्वालिटी 5200-5700, मल्का स्थानीय 5300-5500, बढ़िया 5400-5600, मोठ 3650-4050, अरहर 4550, दाल अरहर दड़ा 6500-8300, चना 5300-5450,

कानपुर

गेहूं 1770/1800, जौ नया 1440/1450, चावल मसूरी 2300/2325, चावल मोटा 2050/2125, सरसों 3300/3400, तिल सफेद 7200/7300, सोया (टीन) 1100/1140, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1280/1300, सरसों खल 1900/1925, पामोलिन 1050/1060, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1060/1080, अलसी खल 3000/3050

लखनऊ

अनाज एवं दाल-दलहनः गेहूं दड़ा 1830/1840, गेहूं शरबती 2250/2350, चावल शरबती सेला 3200/3300, स्टीम 5000/5100, लालमती 2600/3000, चावल (सोना) 2700/2800

चंदौसी

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1100, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.) 1230, फ्लैक 1165, डीएमओ 835, टरपीन लैस बोल्ड 1255

मुजफ्फरनगर

गुड़ (40 किलो): चाकू 1100/1150, खुरपा 1000/1020, लड्डू 1100/1120, रसकट 1000/1020, शक्कर 1125/1140, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (उत्पादन कर सहित): शामली 3860, टिकोला 3870, अफजलगढ़ 3960, धामपुर 3850, चीनी हाजिर 3950/4000

हापुड़

गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 4000/4050, गुड़ (प्रति क्विं.) बाल्टी 2650/2700, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 3600, खलः सरसों 2050/2150, बिनौला 2650/2750, चना छिलका 1800/1850, चोकर मोटा (34 किलो) 560

जयपुर

अनाजः चावल डीबी 6075/6200, गेहूं (मिल) 1630/1670, मक्की 1555/1560, बाजरा 1450/1460, जौ 1670, ग्वार लूज 3675/3700, ज्वार कैटलफीड 1400/1500, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 2300/2400, तेल-तिलहनः सरसों 3450, सरसों एक्सपेलर निवाई 7000, कोल्हू कच्ची घानी टोंक 7200, राइसब्रान डिऑयल्ड कंटीन्यूअस 7700, बिनौला खल जयपुर 2900/2950, आदिलाबाद 2920/2960, खामगांव 2850/2950, खंडवा 2920/2950, डीओसी (टन): सरसों जयपुर 14600, कोटा 14900, अलवर 14900, निवाई 14900

श्रीगंगानगर

गेहूं (पैड) 1760, ग्वार (ढेरी) 3800, जौ (पेड) 1750/1760, सरसों लूज 3450/3500, बिनौला खल 2690/2700

जोधपुर

गेहूं 1650/1730, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4700/4750, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड)3925/3950, ग्वारगम 7950/8000,

रवन्ना

कर रहित (प्रति क्विं): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट) 102, राइसब्रान (अखाद्य) 100, खल सरसों 2000, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 915, लाल 850, कंटीन्यूअस 950, सरसों (टन) 17500, सूरजमुखी (टन) 20000/20100,

फाजिल्का

गेहूं 1800/1810, सरसों 3350/3425, रुई (प्रति मन): (जे-34)2350/2400, कपास देशी 1950/2000, कपास नरमा (क्विं.) 5800/5900, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2450/2500, जे-34 (चिलकी) 2650/2700 *भाषा/एनएनएस*